

**भारत सरकार**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**  
**पशुपालन और डेयरी विभाग**  
**लोकसभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1399**  
**दिनांक 29 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न**

**दूध की कीमतों में वृद्धि**

**1399. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में दूध की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;
- (ख) सहकारी समितियों और निजी डेयरियों द्वारा मूल्य वृद्धि के क्या कारण बताए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार का उपभोक्ताओं के लिए दूध की कीमतों को स्थिर करने हेतु कोई उपाय करने का प्रस्ताव है;
- (घ) सरकार द्वारा बढ़ती लागत के बावजूद डेयरी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ङ) क्या लागत को नियंत्रित करने के लिए चारा राजसहायता योजनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और
- (च) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार की चारा उत्पादन और साइलेज इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु क्या योजना है?

**उत्तर**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**  
**(प्रो.एस.पी. सिंह बघेल)**

- (क) पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार, देश में दूध की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य दुग्ध परिसंघों/हितधारकों के परामर्श से नियमित रूप से देश में दूध की स्थिति की निगरानी करता है। पिछली दुग्ध स्थिति समीक्षा बैठक दिनांक 22.04.2025 को आयोजित की गई थी तथा इस बैठक के दौरान दूध की स्थिति की समीक्षा की गई और हितधारकों के पास पर्याप्त कमोडिटी स्टॉक होने के कारण स्थिति स्थिर पाई गई।
- (ख) दूध की कीमतें सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा उनकी उत्पादन लागत, डेयरी वस्तुओं (सफेद मक्खन, स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) आदि) के स्टॉक तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बाजार शक्तियों के आधार पर तय की जाती हैं।
- (ग) और (घ) डीएचडी देश में दूध की खरीद और बिक्री की कीमतों को नियंत्रित नहीं करता है। कीमतें सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा उनकी उत्पादन लागत और बाजार की शक्तियों के आधार पर तय की जाती हैं। हालाँकि, डीएचडी राज्य सरकार द्वारा किए गए दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण अवसंरचना संबंधी प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने हेतु देश भर में निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है:
1. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** आरजीएम को देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कार्यान्वित किया गया है।
  2. **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):** एनपीडीडी को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है:
    - (i) एनपीडीडी का **घटक "क"** राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दूध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/दूध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्ता वाले

दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढीकरण पर केंद्रित है।

- (ii) एनपीडीडी योजना के **घटक 'ख'** "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है।

3. **डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO):** गंभीर प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण के संबंध में ब्याज सबवेंशन (नियमित तौर पर 2% तथा समय पर भुगतान पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों की सहायता करना।
4. **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF):** एचआईडीएफ पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के सृजन/सुदृढीकरण के लिए 3% की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, और इस प्रकार असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान करता है।
5. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):** उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एसएचजी, धारा 8 कंपनियों और नस्ल सुधार अवसंरचना हेतु राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी और सूअर पालन में उद्यमिता विकास, चारा और नस्ल सुधार पर सघन ध्यान केंद्रित करना।
6. **पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP):** इसका उद्देश्य पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी तथा पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि का एक नया घटक जोड़ा गया है जिससे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) तथा सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।

ये योजनाएँ बोवाइन पशुओं की दुग्ध उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, चारे की उपलब्धता बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में सहायक हो रही हैं। ये पहले दुग्ध उत्पादन की लागत को कम करने और डेयरी फार्मिंग से दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने में भी सहायक हैं।

(ड) और (च) राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) के अंतर्गत, डीएचडी चारा अवसंरचना को मजबूत करने और गुणवत्तापूर्ण चारे की वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उद्यमशीलता संबंधी पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। हे(hay), साइलेज, कुल मिश्रित राशन (TMR), चारा ब्लॉक और बीज ग्रेडिंग इकाइयों की स्थापना के लिए 50% (50 लाख रुपये तक) की पूंजीगत सब्सिडी दो किस्तों में प्रदान की जाती है। अब तक, 129 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनकी अनुमानित स्थापित क्षमता 4,64,500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और जिनकी कुल परियोजना लागत 120.62 करोड़ रुपये है। 52.87 करोड़ रुपये की अनुमोदित सब्सिडी संस्वीकृत की गई है, जिसमें से 15.77 करोड़ रुपये 62 लाभार्थियों को संवितरित किए जा चुके हैं। यह योजना किसानों, ग्रामीण युवाओं, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ, संयुक्त देयता समूहों और धारा 8 कंपनियों सहित निजी क्षेत्र के हितधारकों को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे विकेंद्रीकृत चारा उत्पादन और साइलेज जैसी आधुनिक संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा मिलता है।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने "किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के गठन एवं संवर्धन" योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से 100 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की सफलतापूर्वक स्थापना की है। ये एफपीओ चारा-संबंधी व्यावसायिक कार्यकलापों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं, जिससे संसाधनों तक बेहतर पहुँच, किसानों के सामूहिकीकरण (Collectivization) और मजबूत कृषि-पशुधन मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा मिल रहा है। ये पहले चारे की कीमतों को स्थिर करने, आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता को कम करने तथा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पशुधन उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर रही हैं।

\*\*\*\*\*